आधारभूत ढाँचे के सुदृढ़ीकरण हेतु लिये गए कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय : पार्ट – 1

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा देश के आधारभूत ढाँचे को बल प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए है। मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मुजफ़्फरपुर-सगौली एवं सगौली-वाल्मिकी नगर लाइनों के विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण, उत्तराखंड के सिल्कियारा बेंद बारकोट टनल के निर्माण सहित झांसी-माणकिपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरणको मंज़ूरी देने जैसे निर्णय लिये गए हैं। इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ एवं अन्य प्रमुख बिंदुओं के विषय में हमने संक्षिप्त मनें वर्णन किया है।

मुजफ़्फरपुर - सगौली एवं सगौली – वाल्मिकी नगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण

मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 100.6 किलोमीटर लंबी मुजफ़्फरपुर-सगौली एवं 109.7 किलोमीटर लंबी सगौली-वाल्मिकी नगर लाइनों के विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण परियोजनाओं को मंज़ूरी प्रदान की गई है। इसके लिये क्रमश: 1347.61 करोड़ रुपए और 1381.49 करोड़ रुपए की संपूर्ण लागत को अनुमोदित किया गया है।

- ये परियोजनाएँ बिहार के मुजफ़्फरपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) और पश्चिमी चंपारण (बेतिया) क्षेत्र को कवर करेंगी।

वर्तमान स्थिति

- ये सभी क्षेत्र उत्तरी बिहार के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। इस समय मुजफ़्फरपुर से वाल्मिकी नगर तक यात्री गाड़ियाँ संकुलन और ठहरावों के कारण सबसे अधिक प्रभावित है।
- इस खंड में प्रतिदिन 38 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती हैं।

क्या लाभ होगा?

- अतिरिक्त क्षमता होने से संकुलन कम होगा और न्यूनतम विलंब होने से तीव्रतर एवं विश्विसनीय संचालन संभव होगा। इसके अलावा, इससे अनुरक्षण ब्लॉकों की अधिक उपलब्धता से संरक्षा में भी संवर्द्धन होगा।
- मुजफ़्फरपुर से वाल्मिकी नगर तक समूचे मार्ग को विसंकुलित करने के अलावा दोहरीकरण से क्षमता और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
- वर्ष 2022 तक देश के पूर्वी क्षेत्रों का विकास माननीय प्रधानमंत्री के 'न्यू इंडिया' विज़न को साकार करने की दृष्टि से आवश्यक है। चम्पारण ज़िला नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है, जिससे इस लाइन का दोहरीकरण होने के परिणामस्वरूप पड़ोसी देशों के साथ भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी।
- विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप गाड़ियाँ तीव्र गति से चलेंगी, कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी और टिकाऊ पर्यावरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे ईंधन के आयात पर निर्भरता भी कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा लागत में बचत होगी और देश के लिये विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
- मुजफ़्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्मिकी नगर परियोजनाओं से क्रमश: 24.14 लाख कार्य दिवसों और 26.33 लाख कार्य दिवसों का प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होगा।

चारधाम महामार्ग परियोजना के तहत उत्तराखंड में सिल्कियारा बेंद बारकोट टनल

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा उत्तराखंड में 4.531 किलोमीटर लंबी दो लेन वाली दोतरफा सिल्कियारा बेंद बारकोट टनल (Silkyara Bend - Barkot Tunnel) के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की गई है। इस टनल से निकलने हेतु एक सुरक्षित मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड में धारसू-यमनोत्री सेक्शन पर 25.400 किलोमीटर और 51.000 किलोमीटर के दो प्रवेश मार्ग बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में राजमार्ग संख्या 134 (पुरानी राजमार्ग संख्या 94) के बीच में पड़ेगी। इसका काम इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण मोड के तहत किया जाएगा।
- इसका वित्तपोषण सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनएच (ओ) स्कीम के तहत किया गया है। विशेष बात यह है कि यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना चारधाम परियोजना का हिस्सा है।
- परियोजना निर्माण की अवधि 4 वर्ष है। इसके निर्माण पर 1119.69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। परियोजना का कुल खर्च 1383.78 करोड़ रुपए होगा।
- यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास लिमिटेड (National Highways & Infrastructure Development Corporation

Ltd. -NHIDCL) के ज़रिये सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रयान्वति की जाएगी।

- एनएचआईडीसीएल सरकार की पूरण स्वामतिव वाली कंपनी है, जसिकी स्थापना 2014 में राज्यों से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सड़कों के वकिास के लयि की गई थी।

इससे क्या-क्या लाभ होंगे?

- इस टनल के नरि्माण से चारधाम यात्रा के एक धाम यमुनोत्री तक जाने के लयि हर तरह के मौसम हेतु उपयोगी संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा।
- इससे क्षेत्र के सामाजकि-आर्थकि वकिास के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मलिगा।
- इससे धारसू से यमुनोत्री के बीच सड़क मार्ग की दूरी करीब 20 कलिोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय भी करीब एक घंटा कम हो जाएगा।
- प्रस्तावति टनल के नरि्माण के दौरान बड़ी संख्या में उन पेड़ों को हटाने से बचाया जा सकेगा, जनि्हें 25.600 कलिोमीटर लंबे सड़क मार्ग के उन्नयन के दौरान मूल नक्शे के तहत काटा जाना था।

झांसी - मणकिपुर और भीमसेन – खैरार लाइनों का वद्युतीकरण सहति दोहरीकरण

आर्थकि मामलों की मंत्रमिंडलीय समति (सीसीईए) द्वारा 4955.72 करोड़ रुपए की संपूरण लागत पर 425 कलिोमीटर लम्बी झांसी-माणकिपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों के दोहरीकरण और वद्युतीकरण की परयोजनाओं को अनुमोदति कयि गया है।

- खैरार, खैरार-माणकिपुर और खैरार-भीमसेन की मौजूदा लाइन क्षमता, उपयोगति क्रमशः 126, 160 और 107 प्रतशित है, जसिसे इस खंड में संकुलन होता है और गाड़ियों की गतिधीमी होती है।

इससे क्या-क्या लाभ होंगे?

- इस परयोजना के वरष 2022-23 तक पूरा होने की संभावना है। इन परयोजनाओं में उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, बांदा, चत्रिकूट धाम और मध्य प्रदेश के छतरपुर आदज़िलों को कवर कयि जाएगा। इस दोहरीकरण परयोजना से वपिरीत दशि में गाड़ियों की क्रॉसगि के लयि ठहराव दयि बनि झांसी/कानपुर से आने-जाने वाली गाड़ियों और इलाहाबाद से आने-जाने वाली गाड़ियों का आवागमन सुगम होगा।
- इससे झांसी-सतना और कानपुर-सतना के मार्ग पर यात्री गाड़ियों के समय-पालन और सुगम चालन में सुधार होगा।
- इस परयोजना से अनुरक्षण ब्लॉकों के लयि बेहतर उपलब्धता में सुधार के माध्यम से बेहतर संरक्षा व्यवस्था मुहैया होगी।
- डीएफसी (समर्पति माल गलयिारा) की कनेक्टविटिी भीमसेन स्टेशन के समीप है। इस प्रकार यह मार्ग डीएफसी के लयि फीडर मार्ग के रूप में कार्य करेगा और वस्तुओं, वशिष रूप से कृषि उत्पादों के उपभोक्ता क्षेत्रों तथा नरि्यात के लयि बंदरगाहों तक सुगम संचलन के ज़रयि आर्थकि और औद्योगकि वकिास में सहायक होगा।
- सीमेंट के सुगम संचलन के ज़रयि इस वकिास से सतना में सीमेंट क्लस्टर और अवसंरचना सेक्टर को भी मुख्य रूप से लाभ होगा।
- इस परयोजना से खजुराहो (एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल) तक कनेक्टविटिी में सुधार होगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन के माध्यम से आर्थकि सम्पन्नता आएगी और रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।
- वद्युतीकरण के परणिामस्वरूप गाड़ियाँ तीव्र गतसि चलेंगी, कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी और टकिाऊ पर्यावरण को प्रोत्साहन मलिगा। इसके अलावा, इससे ईंधन आयात पर नरि्भरता में कमी होगी, जसिके परणिामस्वरूप रेलों के लयि ऊर्जा लागत में बचत होगी और देश के लयि वदिशी मुद्रा की बचत होगी।
- इसके अलावा, इन परयोजनाओं से नरि्माण के दौरान लगभग 102 लाख कार्य दवि्सों का प्रत्यक्ष रोज़गार सृजति होगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/some-important-decisions-taken-for-the-strengthening-of-the-infrastructure-part-1